



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2012/चैत्र 3, 1934

No. 77]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2012/CHAJTRA 3, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

विषय : चीन और स्विटजरलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित “विटामिन ए” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 15/7/2011-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है), और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटिवस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है), ने 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/11/2005-डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. तथा स्विटजरलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामीटेट (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/11/2005-डीजीएडी के तहत जारी किए। जांच परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार ने 30 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 112/2007-सी.शु. के तहत पाटनरोधी शुल्क तथा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया।

2. यतः मै. पिरामल हेल्थ केयर लि., पूर्व में मै. निकोलस पिरामल इंडिया लि., के नाम से ज्ञात, चीन जन. गण. तथा स्विटजरलैंड के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामीटेट का पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पुष्टिकृत आवेदन दायर किया है और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग

3. यह आवेदन विटामिन-ए पामीटेट के उत्पादकों की ओर से मै. पिरामल हेल्थ केयर लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र ज्ञात उत्पादक है और वह भारत में संबद्ध वस्तु का संपूर्ण उत्पादन करता है। अतः याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने के आधार को पूरा करता है और वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. मूल जांच में शामिल उत्पाद विटामिन-ए पामीटेट है ! यह एक निर्णागक समीक्षा होने के कारण इस जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद है । विचाराधीन उत्पाद विटामिन-ए पामीटेट के रूप में परिभाषित है जिसमें सभी क्षमताओं और स्वरूपों में विटामिन-ए पामीटेट 1.7 एम आई यू/ग्राम तथा विटामिन-ए पामीटेट 1.0 एम आई यू/ग्राम (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) शामिल है । यह उत्पाद उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय-29 के शीर्ष सं. 293621.00 तथा आई टी सी एच एस वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है । घरेलू उद्योग ऐसे विटामिन-ए पामीटेट का उत्पादन भी करता है जिसमें समान विशेषताएं तथा विनिर्देशन होते हैं । वर्तमान जांच पूर्व में लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद पाटनरोधी नियमानुसार विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" है ।

जांच की शुरूआत

5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार दायर विधिवत पुष्टिकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के बारे में लागू शुल्क निरंतर जारी रखने की जरूरत की समीक्षा हेतु निर्णायक समीक्षा शुरू करते हैं ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसा शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

शामिल उत्पाद

6. इस जांच में शामिल देश चीन जन गण तथा स्विटरजरलैंड हैं जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है ।

जांच अवधि

7. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 (12 माह) तक है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा जांच अवधि शामिल है । पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है ।

प्रक्रिया

8. इस समीक्षा में 14 सितंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/11/2005-डी जी ए डी (मूल मामले की जांच का अंतिम जांच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं । नियमावली के

नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

9. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत स्थित दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों तथा प्रयोक्ताओं को अलग से लिखा जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत करा सकें ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, कक्ष-सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से नीचे निर्धारित समयावधि के भीतर जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है ।

समय सीमा

10. वर्तमान समीक्षा से संबंधितकोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जिसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधर पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

11. वर्तमान मामले में समर्त हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और प्रश्नावली का उत्तर दायर करने तथा इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर पाटनरोधी उपाय जारी रखने या अन्यथा की जरूरत के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

12. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे 2 अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में चिन्हित (शीर्षक, सूचकांक, पृष्ठ सं. आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में चिन्हित अन्य सैट (शीर्षक, सूचकांक, पृष्ठ सं. आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत समर्त सूचना पर स्पष्ट तौर पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी भाग पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए ।

13. प्रस्तुत की गई जिस सूचना पर कोई चिन्हांकन नहीं होगा, उसे अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसी किसी गोपनीय सूचना के बारे में जांच करने की अन्य हितबद्ध

पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे । गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण, प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

14. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता के लिए प्रस्तुत सूचना के साथ एक सकारण दस्तावेज उपलब्ध करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव क्यों नहीं है ।

15. अगोपनीय रूपांतरण गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के अधार पर अधिमानतः सूचीबद्ध या अधिनिहित/सारांशीकृत गोपनीय सूचना की अनुलिपि होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादित परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; ऐसे कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए कि इसका सारांश क्यों संभव नहीं है ।

16. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो ऐसी सूचना की अनदेखी की जा सकती है ।

17. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के बारे में सकारण विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता । संतुष्ट होने तथा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इसका प्रकटन किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

18. नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

असहयोग

19. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2012

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of Vitamin A Palmitate originating in or exported from China and Switzerland.

F. No. 15/7/2011-DGAD.—

1. Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Vitamin A Palmitate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Switzerland vide notification No 14/11/2005 -DGAD dated 14th September 2007. The Authority issued final findings vide notification No 14/11/2005- -DGAD dated 14th September 2007. On the basis of the findings, the Central Government imposed antidumping duty and definitive antidumping duty vide Notification No 112 /2007-Cus. Oct. 30, 2007

2. Whereas M/s Piramal Healthcare Ltd previously known as, M/s Nicolas Piramal India Ltd. on behalf of the producers of Vitamin A Palmitate, has filed a duly substantiated application in accordance with the Act and the AD Rules before the Authority alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of Vitamin A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties.

Domestic industry

3. The application has been filed by M/s Piramal Healthcare Ltd on behalf of the producers of Vitamin A Palmitate. The applicant is the sole known producer of subject goods in India and accounts for complete production of subject goods in India. The petitioner, therefore, satisfies the standing to file the present petition and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article

4. The product involved in the original investigation was Vitamin A Palmitate. This being a Sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original

investigation. The product under consideration is defined as Vitamin A Palmitate, which covers Vitamin A Palmitate 1.7MIU/gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/gm (herein after termed as the “subject goods”) in all its strengths and forms. The product is classified under heading No. 293621.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. The domestic industry also produces ‘Vitamin A Palmitate having similar characteristics and specifications. The present investigation is a Sunset review of the anti dumping duty earlier imposed. Therefore, the Authority considers that the product being manufactured by the domestic industry is ‘like article’ to the product under consideration as per the AD Rules

Initiation:

5. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods from subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Countries involved:

6. The countries involved in this investigation are China PR and Switzerland also referred to as subject countries.

Period of Investigation:

7. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st January 2011 to 31st December 2011 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2008-09, 2009-10, 2010-11 & POI. The data beyond period of investigation may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

Procedure:

8. The review covers all aspects of Notification No 14/11/2005 -DGAD dated 14th September 2007 (final findings of the original investigation) and notification dated 10th Feb 2012.. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information:

9. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product

are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Designated Authority, Government of India, Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties Department of Commerce Room
No.240, Udyog Bhawan, New Delhi-110107.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit:

10. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

11. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis.

12. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

13. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

14. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

15. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

16. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

17. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

18. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

19. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority